www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 108 | जौनपुर मंगलवार, 02 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वंदे मातरम पर रोक ब्रिटिश राज की याद दिलाती है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पूर्व बुलेटिन पर आपत्ति जताई, जिसमें सदन में वंदे मातरम और जय हिंद सहित विभिन्न नारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सलाह दी गई थी। चतुर्वेदी ने एएनआई को बताया कि इन नारों परष्प्रतिबंध लगाना ब्रिटिश काल के शासन जैसा है और उनकी पार्टी इस मामले पर सचिवालय से जवाब मांगेगी। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा राज्यसभा सचिवालय और केंद्र सरकार से जवाब मांगना है कि वंदे मातरम और जय हिंद कहना कब से शिष्टाचार और नियमों का उल्लंघन बन गया। यह ब्रिटिश काल की शासन–व्यवस्था जैसा है। नोटिस को ष्राष्ट्र–विरोधीष बताते हुए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वंदे मातरम और जय हिंद हमारे देश और इसके स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये नारे लगाना देश प्रेम के कारण है, लेकिन अब वे जो कर रहे हैं वह राष्ट्र–विरोधी है। केंद्र सरकार को राज्यसभा में जय हिंदी और वंदे मातरम के लिए जारी किया गया नोटिस वापस लेना चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वुशु महासंघ के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली एमेच्योर वुशु एसोसिएशनके खिलाफ भारतीय वुशु एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए डिसएफिलिएशन नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इससे एसोसिएशन को राष्ट्रीय और अंतर–राज्यीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों का चयन जारी रखने की अंतरिम राहत मिल गई है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 24 जुलाई के डिसएफिलिएशन नोटिस को चुनौती देने वाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 नवंबर को यह आदेश पारित किया। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक, 24.07.2025 के विवादित डिसएफिलिएशन नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह भी निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी भी राष्ट्रीय/अंतर–राज्यीय आयोजन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली से एथलीटों की सूची का चयन/भेजने का हकदार होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिता राव द्वारा प्रस्तुत डीएडब्ल्यूए ने तर्क दिया कि यह विघटन गैरकानूनी था क्योंकि इसे डब्ल्यूएआई की आम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जो महासंघ के संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत ऐसी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत एकमात्र प्राधिकारी है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 6 के तहत कारण बताओ नोटिस, सदस्य के स्पष्टीकरण पर विचार और दो–तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित आम सभा के निर्णय की आवश्यकता होती है। के अनुसार, यह मामला कभी भी आम सभा के समक्ष नहीं रखा गया,।

पराजय की निराशा से बाहर आए विपक्ष और संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाए : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सत्र केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्र को तेज गति से प्रगति की ओर ले जाने की ऊर्जा देने वाला अवसर है। पीएम मोदी ने कहा, ष्संसद का यह शीतकालीन सत्र केवल कोई रिवाज नहीं है। यह देश को विकास की ओर तेजी से बढ़ाने में नई ऊर्जा भरेगा। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।ष पीएम मोदी ने लोकतंत्र की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूती से निभाया है। उन्होंने कहा, ष्भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र की उमंग और उत्साह समय–समय पर स्पष्ट दिखाई देता है, जिससे लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता है।ष पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया और इसके साथ ही कहा कि कई दल पराजय के कारण परेशान हैं। विपक्ष को पराजय की निराशा से निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, ष्मुझे लगा था कि बिहार चुनाव खत्म हुए कुछ समय हो गया है, तो चीजें बदल गई होंगी, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनीं और अब मुझे लगता है कि उनकी हार उन्हें अभी भी परेशान कर रही है।ष उन्होंने कहा, ष्यह सत्र इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि संसद देश के लिए क्या सोचती है और क्या करने वाली है। विपक्ष अपना दायित्व निभाए और मजबूत मुद्दे उठाए। पराजय की निराशा से बाहर आए।ष प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और उसकी आर्थिक मजबूती को बेहद ध्यान से देख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है और इसका गति पकड़ना विकसित भारत के सपने को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि हार की निराशा फोकस में नहीं होनी चाहिए और यह जीत के जश्न में भी नहीं बदलनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के तौर पर हमें देशवासियों की जिम्मेदारी और उम्मीदों को बैलेंस के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। यह मुश्किल काम है, लेकिन हमें यह करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को पद संभालने पर बधाई भी दी।

क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धान क्रय केंद्र पर आने वाले हर अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच जाए। सोमवार को धान खरीद की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीद की गति तेज हो और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कॉमन धान का एमएसपी 2,369 रुपए और ग्रेड–ए का 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹69 अधिक है। अब तक 4,227 खरीद केंद्र संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 5,000 की जाए, ताकि किसानों को अपने गांव–कस्बे के निकट ही सुविधा उपलब्ध हो सके। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 1,984 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भुगतान में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि मिड–डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एफआरके सप्लाई सुचारु रखने हेतु वेंडरों की संख्या बढ़ाई जाए और तकनीकी अड़चनों का तत्काल समाधान किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक लगभग 2,130 मीट्रिक टन एफआरके गुणवत्ता परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ है।

नगालैंड की परंपराएं भारत के सांस्कृतिक ताने–बाने को मजबूत करती हैं : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नगालैंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी और कहा कि पूर्वोत्तर राज्य की जीवंत परंपराएं और वहां के लोगों की जुझारू भावना राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने–बाने को मजबूत करती है। नगालैंड का गठन एक दिसंबर, 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में किया गया था। तब से एक दिसंबर को प्रतिवर्ष नगालैंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गृह मंत्री शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नगालैंड की बहनों और भाइयों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की जीवंत परंपराएं और इसके लोगों की जुझारू भावना हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने–बाने को मजबूती प्रदान करती है। गृह मंत्री शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'नगालैंड की बहनों और भाइयों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की जीवंत परंपराएं और इसके लोगों की जुझारू भावना हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने–बाने को मजबूती प्रदान करती है। कामना है कि नगालैंड शांति, प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े।'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगालैंड के लोगों को दी राज्य स्थापना दिवस की बधाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नगालैंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी और सतत विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए राज्य की सराहना की। नगालैंड की स्थापना एक दिसंबर 1963 को हुई थी। मुर्मू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''नगालैंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई! समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नगालैंड सतत विकास में सराहनीय प्रगति कर रहा है।'' राष्ट्रपति ने कहा कि इसकी जनजातीय विविधता और अनोखी विरासत गौरवान्वित करने वाली है। साथ ही उन्होंने ''नगालैंड के लोगों के उज्ज्वल, समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य'' की कामना की। समृद्ध संस्कृति और बेशुमार प्राकृतिक सुंदरता से धन्य, नगालैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लगातार सराहनीय प्रगति कर रहा है। इसकी आदिवासी विविधता और अनोखी विरासत गर्व का स्रोत बनी हुई है। मैं नगालैंड के लोगों के उज्ज्वल, समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नगालैंड के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं। नगालैंड राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता से धन्य है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राज्य आगे बढ़ता रहे और इसके लोगों को स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। नगालैंड को 1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य के तौर पर मान्यता दी गई थी और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद नगा इलाका असम का हिस्सा बना रहा, लेकिन जल्द ही एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें नगा जनजातियों की राजनीतिक एकता की मांग की गई और कट्टरपंथी ग्रुप भारतीय संघ से पूरी तरह अलग होने की मांग कर रहे थे। 1957 में असम के नगा हिल्स इलाके और तुएनसांग फ्रंटियर डिवीजन को भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में मिला दिया गया। 1960 तक यह तय हो गया था कि नगालैंड भारतीय संघ का एक हिस्सा बनेगा।

गुटखा–पान मसाला पर कड़ा प्रहार नई कर व्यवस्था से राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगा बूस्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के दौरान तंबाकू से संबंधित वस्तुओं पर श्सीन टैक्सश लगाने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में श्स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025श पेश किया। इस विधेयक में रक्षा और जन स्वास्थ्य व्यय के वित्तपोषण के लिए पान मसाला और गुटखा निर्माताओं पर एक कठोर नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक के अनुसार, प्रस्तावित उपकर पान मसाला और गुटखा सहित विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के लिए स्थापित मशीनों या प्रक्रियाओं पर लगाया जाएगा। इसमें कहा गया है, ष्स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक में उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है जिनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तु, अर्थात् पान मसाला, का निर्माण या उत्पादन किया जाता है, चाहे वह मैन्युअल रूप से हो या हाइब्रिड प्रक्रियाओं के माध्यम से।ष यह विधेयक एक व्यापक अनुपालन और प्रवर्तन ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह कर योग्य व्यक्तियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों के स्वामी, धारक, संचालक या नियंत्रक हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से हों या श्रमिकों या अनुबंधित संस्थाओं के माध्यम से। उपकर उत्पादन की मात्रा की परवाह किए बिना देय होगा, और देयता मशीन की गति, क्षमता या निर्माताओं द्वारा घोषित प्रक्रिया मापदंडों पर आधारित होगी। विधेयक में आगे कहा गया है कि, ष्उपकर मशीनों या अन्य प्रक्रियाओं की उत्पादन क्षमता से जुड़ा है, न कि ऐसी निर्दिष्ट वस्तुओं के वास्तव में उत्पादित मात्रा से।ष यह विधेयक केंद्र को विशेष परिस्थितियों में निर्धारित राशि से दोगुने तक उपकर बढ़ाने का अधिकार देता है और जनहित में अधिसूचना के माध्यम से छूट प्रदान करता है। उपकर के माध्यम से एकत्रित धनराशि भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी ।

भारत सरकार द्वारा प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को उत्तरप्रदेश के समस्त स्कूल कॉलेज को नशा मुक्त कराने के महाअभियान का सौंपा गया दायित्व : अयोध्या श्री राम नगरी से होगी इसकी शुरूआत

दैनिक देश की उपासना ब्यूरो

अयोध्या। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भारत सरकार के द्वारा उत्तरप्रदेश के समस्त कॉलेज स्कूल को नशा मुक्त के महाअभियान का दायित्व सौंपा गया है जिसका शुभारम्भ जनपद अयोध्या से किया जाएगा। बता दे कि ब्रह्माकुमारी संस्था के हेडक्वाटर माउंटआबू से विशेष (डॉ. वनारसी साह सीक्रेट्री मेडिकल विगंस),(डॉ. प्रताप मिडडा वाइस प्रेसिडेंट) के साथ साथ अनेक विभूतियों का आगमन अयोध्या में हो रहा हैं ।उक्त सभी लोगों द्वारा इस योजगा का शुभारम्भ श्री राम जन्मभूमि के दर्शन एवं आशीर्वाद लेने के बाद किया जाएगा ।दर्शन के उपरान्त अयोध्या के विशिष्ट संतो महंतों का आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं प्राप्त की जाएगी , इस कार्यक्रम में अयोध्या क्षेत्र के स्थानीय सेवा केंद्र संचालक बी. के. मुकेश भाई के साथ साथ उनके विशिष्ट सहयोगी भाई, बहनों (ई. रवि तिवारी अयोध्या क्षेत्रीय संयोजक विदेश संपर्क विभाग) (राधेश्याम त्यागी भाई) बीजेपी से एवं (चंद्रशेखर तिवारी भाई) ,एवं स्थानीय समस्त समस्त ब्रह्माकुमारी परिवार, के साथ इस प्रोग्राम को दिनांक 4/12/2025 को सुबह 7:30 अयोध्या के दर्शन नगर स्थित ब्रह्माकुमारी संस्था के स्थान से शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक अच्छी पहल होगी और आम जन मानस को इसका लाभ मिलेगा।

आशा है कि सत्र को उत्पादक बनाने में सार्थक योगदान देंगे सदस्य : ओम बिरला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले उम्मीद जताई कि सदन के सदस्य लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करेंगे और अपनी सक्रिय भागीदारी से इस सत्र को उत्पादक बनाने में सार्थक योगदान देंगे। बिरला ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया, 18वीं लोकसभा का छठा सत्र (शीतकालीन सत्र) आज से आरंभ हो रहा है। संसद राष्ट्र की अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। बिरला ने कहा कि संसद का प्रत्येक सत्र हमें कर्तव्य–निष्ठा, संयम और लोककल्याण की उस प्रेरणा की ओर भी उन्मुख करता है, जो जनप्रतिनिधित्व की भावना को और गहन बनाती है। उन्होंने कहा, आशा है कि सभी सदस्य लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करेंगे और अपनी सक्रिय भागीदारी से इस सत्र को उत्पादक बनाने में सार्थक योगदान देंगे।

शपथ ग्रहण के साथ ही विधायकों ने रोजगार, पलायन रोकने और जनहित पर किया फोकस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार शुरू हुआ, जिसमें विधायकों ने शपथ ली। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ–साथ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का विधानसभा पोर्टिको में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ ग्रहण सत्र की शुरुआत मंत्रियों और उसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों से की। सत्र से पहले, नवनिर्वाचित विधायकों ने बिहार की जनता और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जद(यू) के नवनिर्वाचित विधायक विनय कुमार चौधरी ने अपने भाषण में जन कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। इससे बिहार की जनता की सेवा पर पार्टी का जोर झलकता है। लोजपा–रामविलास के नवनिर्वाचित विधायक विष्णु देव पासवान ने बिहार के युवाओं के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा, ष्मैं रोजगार के अवसर पैदा करना चाहता हूँ ताकि बिहार के युवाओं को पलायन न करना पड़े। राजनीति के कारण बिहार को वह विकास नहीं मिला जिसका वह हकदार था।ष उन्होंने राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया। मौजूदा विधानसभा में राजद से निर्वाचित विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्य में एनडीए की जीत का विरोध किया। उन्होंने जनता की चिंताओं को आवाज देने के विपक्ष के संकल्प पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा मनोबल ऊँचा है और जनता ने हमें वोट दिया है। उन्होंने (एनडीए) जनादेश से नहीं, बल्कि वोट चोरी से सरकार बनाई है। हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन चिंताओं को उठाने की हमारी ताकत कम नहीं होगी। बिहार विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र की विधायक बनीं भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह एक ष्बड़ा दिनष और एक नए जीवन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज शपथ लेने के बाद मैं विधायक बन जाऊँगी। आज एक नए जीवन की शुरुआत है। पिछले महीने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) विधायकों को कैबिनेट विभाग आवंटित किए, और गृह विभाग सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सौंप दिया।

संपादकीय

ट्रेड यूनियनों का संघर्ष

मौजूदा हालात में सरकारी नीतियों से प्रभावित किसी तबके लिए संघर्ष करना या अपनी मांगें मनवाना आसान नहीं रह गया है। इसलिए चार श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का संघर्ष भी बहुत प्रभाव छोड़ पाएगा, इसकी संभावना कम है। संसद से पारित होने के बाद चार श्रम संहिताओं को लागू करने में सरकार को लगभग छह साल लगे, तो उसका यही संकेत है कि इनको लेकर संबंधित पक्षों के बीच कैसे टकराव की स्थिति रही है। सत्ता पक्ष की हालिया चुनावी सफलताओं के बाद संभवतरू केंद्र ने महसूस किया है कि इन संहिताओं को लागू करने का यह अनुकूल मौका है। केंद्र का दावा है कि इन संहिताओं के जरिए पुराने पड़ गए श्रम कानूनों को आधुनिक और मौजूदा वैश्विक प्रतिमानों के अनुरूप बनाया गया है। दावा तो यह भी है कि इनमें श्रमिकों के कल्याण के नए और प्रभावी उपाय शामिल किए गए हैं। मगर दस ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की प्रतिक्रिया पर गौर करें, तो यह साफ होता है कि श्रम क्षेत्र के अनेक प्रमुख हितधारक ऐसे दावों से सहमत नहीं हैं। उनकी दलील है कि इन संहिताओं का मकसद मजदूरों एवं कर्मचारियों की सामूहिक सौदेबाजी की वैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना है। इन संहिताओं के तहत ट्रेड यूनियन बनाना, उनकी सामूहिक शक्ति के जरिए अपनी मांगों को रखना या हड़ताल पर जाना बेहद कठिन हो जाएगा। यानी श्रमिक वर्ग पूरी तरह प्रबंधन और सरकार की सदाशयता पर निर्भर हो जाएगा। संयुक्त मंच ने याद दिलाया है कि इन संहिताओं के खिलाफ गुजरे वर्षों में उसने कई आंदोलन किए। मंच ने इसी गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिल कर देश भर में विरोध जताने का एलान किया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन के कई अन्य कार्यक्रम भी उसने घोषित किए हैं। यह निर्विवाद है कि मौजूदा हालात में सरकारी नीतियों से प्रभावित किसी तबके लिए संघर्ष करना या अपनी मांगें मनवाना आसान नहीं रह गया है। इसलिए ट्रेड यूनियनों का संघर्ष भी बहुत प्रभाव छोड़ पाएगा, इसकी संभावना कम है। फिर भी बिना उन्हें भरोसे में लिए श्रम संहिताओं को लागू कर सरकार ने टकराव का एक नया मोर्चा खोल दिया है। बेहतर होता, भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) की बैठक बुलाकर अधिकतम सहमति बनाने की कोशिश की जाती। मगर केंद्र ने इसकी जरूरत नहीं समझी। इससे श्रम एवं पूंजी के बीच नया तनाव पैदा हो सकता है।

मजदूरों की मुश्किलें

अजीत द्विवेदी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक स्थायी दावा होता है कि वह जो भी काम कर रही है वह सबसे बड़ा काम है या ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। तभी छह साल पहले 2019 में भारतीय संसद से पास चार श्रम कानूनों को लागू करते हुए ऐसा ही दावा किया गया है। हैरानी की बात है कि अनेक मीडिया समूह भी अपने संपादकीय में इन कानूनों को इसी रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में किसी भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ध्यान रहे अब तक 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की ओर से लागू किए गए उदारीकरण के फैसले को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता रहा है। अब उसकी जगह श्रम कानूनों को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सबसे बड़ा कथित आर्थिक सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को वैसे ही बदल पाएगा, जैसे 1991 के आर्थिक सुधारों ने बदला था? और क्या इससे श्रमिकों की हालत में कोई गुणात्मक परिवर्तन आएगा? इसकी संभावना कम है।

बुनियादी रूप से ये चारों कानून कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। इनकी जो एकमात्र बड़ी खासियत दिखाई दे रही है वह ये है कि पहले से मौजूद 29 केंद्रीय कानूनों को इन चार कानूनों में समेटा गया है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि पहले इन 29 कानूनों की वजह से उद्योग व कारोबारी समूहों को इनके अनुपालन में समस्या आती थी तो दूसरी ओर श्रमिकों के लिए जरूरी लाभ उपलब्ध कराना मुश्किल होता था। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इससे मजदूरों को कैसे फायदा होगा? इस सवाल पर विचार से पहले चारों कानूनों के बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। ये चार कानून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता हैं। पहला कानून यानी वेतन संहिता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मजदूरों को एक निश्चित वेतन मिले, वेतन समय पर मिले और वह उचित हो। पहले वेतन, भत्ता, पेंशन, बोनस आदि के लिए अलग अलग कानून थे, जिससे परेशानी होती थी। इसमें एक खास बात यह है कि महिलाओं को पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। हालांकि उचित और समय पर वेतन मिलना कैसे सुनिश्चित होगा यह कानून लागू होने के बाद पता चलेगा। दूसरा कानून औद्योगिक संबंध संहिता हैं, जिसके तहत कर्मचारी और कंपनी के संबंधों की व्याख्या की गई है और साथ ही दोनों के बीच विवाद के त्वरित निपटान की व्यवस्था भी बनाई गई है। इसमें हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के नियम भी शामिल किए गए हैं और सबसे ज्यादा विरोध इसी नियम का हो रहा है। तीसरा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता का है, जिसमें असंगठित मजदूरों, ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले लोग, जिन्हें गिग वर्कर्स कहा जा रहा है उनके लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में कहा गया है कि कंपनियां इनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाएंगी। इस कानून के जरिए स्वास्थ्य, बीमा और मातृत्व सुविधा जैसे लाभों को हासिल करना आसान बनाया जाएगा। चौथा और अंतिम कानून व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता है, जिसमें कर्मचारियों, मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है साथ ही कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियों को दूर करके उसे बेहतर बनाने के उपाय भी किए गए हैं। पहले से मौजूद 13 कानूनों मिला कर इसे बनाया गया है। इसमें महिलाओं के रात में काम करने का प्रावधान भी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह अद्भुत संतुलन वाला कानून है, जिससे मजदूरों और कर्मचारियों को भी फायदा होगा तो उद्योग समूहों को भी लाभ होगा। सवाल है कि जब दोनों के लिए फायदे वाला कानून है तो इसे लागू करने में सरकार को छह साल क्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि अगर ये कानून मजदूरों के हित में हैं तो देश के ज्यादातर बड़े मजदूर संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में संसद में पास करने से लेकर इनके नियम बना कर इन्हें लागू करने तक जब भी इन कानूनों की बात होती है तो दावा किया जाता है कि इनसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी, समय पर व उचित वेतन मिलेगा तो दूसरी ओर कंपनियों को एक ऐसा सरल ढांचा मिलेगा, जिसके अनुपालन में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह सिर्फ सदिच्छा है। वास्तव में इसका कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा। परंतु उससे पहले इस कानून के कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनको मजदूर फ्रेंडली कतई नहीं माना जा सकता है। उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों को नियमों में बांधने, उनके विरोध करने की क्षमता को कम करने और उनकी नौकरी को असुरक्षित बनाने के प्रावधान इन कानूनों में निहित हैं। मिसाल के तौर पर औद्योगिक संबंध संहिता में प्रावधान किया गया है कि तीन सौ तक मजदूर और कर्मचारी वाला उद्योग सरकार की अनुमति के बगैर छंटनी कर सकता है। पहले एक सौ मजदूरों तक की कंपनियों को यह छूट मिली थी। यह दायरा बढ़ाने का मतलब है कि देश की ज्यादातर कंपनियां और उद्योग अपने यहां पहले से ज्यादा आसानी से छंटनी कर पाएंगे।

भारत का आर्थिक विकास- सहकारिता से समृद्धि की ओर

प्रह्लाद

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों का अनुपालन करते हुए ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिक आपस में भाई–चारे के साथ मिलजुलकर रहते आए हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो सहकार की भावना हम भारतीयों के डीएनए में है। इसी विषय के दृष्टिगत एक बार पुनः आज भारत के प्रत्येक गांव को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने की लिए समस्त गावों को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। "सहकार से समृद्धि" का नारा भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिया गया है। भारत में आज सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकिं भारत में सहकारी समतियां, स्व–सहायता, स्व–जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, न्याय एवं एकजुटता जैसे भारतीय मूल्यों के आधार पर कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही, जिन 7 सिद्धांतों के आधार पर इन समितियों के कार्य करने की अपेक्षा रहती है, उससे इन समितियों के सफल होने की सम्भावना बढ़ जाती है। यह 7 सिद्धांत हैं – खुली और स्व्वैच्छिक सदस्य्यताय लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य्यों की भागीदारीय सदस्य्यों की आर्थिक भागीदारीय स्व्वायत्त्तता और स्व्वतंत्रताय शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचनारू कोआपरेटिव के बीच सहयोगय समुदाय के प्रति सरोकार। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्ण मिलजुल कर समान स्तर पर आपसी आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। समृद्धि केवल धन–संपत्ति से कहीं अधिक है, यह तब होती है जब सभी लोगों को फलने–फूलने का अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। समृद्धि एक समावेशी समाज पर आधारित होती है, जिसमें एक मजबूत सामाजिक अनुबंध होता है जो प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करता है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाना और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसा संगठन है जो सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। भारत में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 से हुई है एवं तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है। कुछ अत्यधिक सफल रही हैं, जैसे अमूल डेयरी, परंतु इस प्रकार की सफलता की कहानियां बहुत कम ही रही हैं। कहा जाता है कि देश में सहकारिता आंदोलन को जिस तरह से सफल होना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। बल्कि, भारत में सहकारिता आंदोलन में कई प्रकार की कमियां ही दिखाई दी हैं। देश की अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही यदि 5 लाख करोड़ अमेरिकी डालर के आकार का बनाना है तो देश में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाना ही होगा। इस दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया गया है। विशेष रूप से गठित किए गए इस सहकारिता मंत्रालय से अब "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना के साकार होने की उम्मीद भी की जा रही है। भारत में सहकारिता आंदोलन का यदि सहकारिता की संरचना की दृष्टि से आंकलन किया जाय तो ध्यान में आता है कि देश में लगभग 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। इन समितियों में कुल सदस्य संख्या लगभग 28 करोड़ है। हमारे देश में 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जैसे, देश में 1.5 लाख प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 93,000 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं। ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कार्य करती हैं। इन दोनों प्रकार की लगभग 2.5 लाख सहकारी समितियां ग्रामीण इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाकर इन इलाकों की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अपने दायरे में लिए हुए है। उक्त के अलावा देश में सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं और यह तीन प्रकार की हैं। एक तो वे जो अपनी सेवाएं शहरी इलाकों में प्रदान कर रही हैं। दूसरी वे हैं जो ग्रामीण इलाकों में तो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, परंतु कृषि

क्षेत्र में ऋण प्रदान नहीं करती हैं। तीसरी वे हैं जो उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। इसी प्रकार देश में महिला सहकारी साख समितियां भी कार्यरत हैं। इनकी संख्या भी लगभग एक लाख है। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली सहकारी साख समितियां भी स्थापित की गई हैं, इनकी संख्या कुछ कम है। ये समितियां मुख्यतः देश में समुद्र के आसपास के इलाकों में स्थापित की गई हैं। देश में बुनकर सहकारी साख समितियां भी गठित की गई हैं, इनकी संख्या भी लगभग 35,000 है। इसके अतिरिक्त हाउसिंग सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। संचालन और कार्यों की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः छह प्रकार की सहकारी समितियां होती हैं। इनमें उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, कृषक सहकारी समितियां, ऋण सहकारी समितियां और सहकारी आवास समितियां शामिल हैं। उक्त वर्णित विभिन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी समितियों के अतिरिक्त देश में सहकारी क्षेत्र में तीन प्रकार के बैंक भी कार्यरत हैं। एक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी संख्या 1550 है और ये देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत हैं। दूसरे, 300 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं तीसरे, प्रत्येक राज्य में एपेक्स सहकारी बैंक भी बनाए गए हैं। उक्त समस्त आंकडें वर्ष 2021–22 तक के हैं। 29 जून, 2022 को भारत सरकार द्वारा 63,000 क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में सहकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं। दुग्ध क्षेत्र में अमूल सहकारी समिति लगभग 70 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई है, जिसे आज भी सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता के रूप में गिना जाता है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई समितियों द्वारा रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित किए गए हैं। सहकारी क्षेत्र में एक विशेषता यह पाई जाती है कि इन समितियों में सामान्यतः निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। सहकारी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं। जैसे, सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय समय पर उजागर होती रही हैं। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में पेशेवर प्रबंधन का अभाव रहा है एवं ये बैंक पूंजी बाजार से पूंजी जुटा पाने में भी सफल नहीं रहे हैं। अभी तक चूंकि सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र का अभाव था एवं केंद्र सरकार द्वारा अब किए गए नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र के संस्थानों को नियंत्रित करने में कसावट आएगी एवं इन संस्थानों का प्रबंधन भी पेशेवर बन जाएगा जिसके चलते इन संस्थानों की कार्य प्रणाली में भी निश्चित ही सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। अब हमें दूध के पावडर के आयात की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु दूध के उत्पादन के मामले में भारत के कुछ भाग ही, जैसे पश्चिमी भाग, सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। देश के उत्तरी भाग, मध्य भाग, उत्तर–पूर्व भाग में दुग्ध उत्पादन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है।

सत्र छोटा करके इस सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था को भी खत्म करने की तैयारी

शकील

संसद ही एक ऐसी जगह होती है जहां केवल विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल में अच्छे– अच्छे मंत्री भी कई बार लाजवाब हो जाते थे। सदस्य तैयारी के साथ आते थे। अपने क्षेत्र के बारे में पूछे गए सवालों के साथ तथ्यात्मक सप्लीमेंट्री सवाल लाते थे। मगर अब प्रश्नकाल चलता ही नहीं। संसद का सत्र अभी कुछ साल पहले तक मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर हुआ करता था। मगर अब प्रधानमंत्री सदन में आते नहीं। प्रधानमंत्री सदन के नेता कहलाते हैं। जिस सदन से होते हैं। नरेन्द्र मोदी लोकसभा में नेता सदन हैं। मगर वे संसद में होते हुए भी सदन में नहीं आते। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मनमोहन सिंह से लेकर वाजपेयी और सभी प्रधानमंत्री पूरे संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों में रहते थे। अपने मंत्रालय से संबंधित सवालों के जवाब देते थे। और विपक्ष द्वारा उठाए गए अन्य सवालों पर भी बोलते थे। संसद सत्र खबरों से भरपूर हुआ करता था। मगर अब संसद की प्रेस गैलरी भी खाली पड़ी रहती है। प्रधानमंत्री नहीं होते, सरकार किसी विषय पर चर्चा को तैयार नहीं होती, पीठासीन अधिकारी सत्र चलाने के बदले उसे जल्दी से स्थगित करने का तरीका अपनाते हैं, नतीजा शुरू होने के कुछ ही देर बाद सदन स्थगित। और सदन के कम समय चलने के बाद अब स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार सत्र भी कम अवधि का बुलाने लगी है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। मगर सिर्फ तीन हफ्ते का। एक दिसम्बर से शुरू होगा और 19 दिसम्बर को खत्म। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए संसद का सत्र छोटा कर रही है। संसद ही एक ऐसी जगह होती है जहां केवल विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। प्रश्नकाल में अच्छे– अच्छे मंत्री भी कई बार लाजवाब हो जाते थे। सदस्य तैयारी के साथ आते थे। अपने क्षेत्र के बारे में पूछे गए सवालों के साथ तथ्यात्मक सप्लीमेंट्री सवाल लाते थे। मगर अब प्रश्नकाल चलता ही नहीं। संसद कवर करने वाले पत्रकारों के लिए प्रश्नकाल सबसे ज्यादा खबरों वाला और जीवंत एक घंटा हुआ करता था। हर पत्रकार उस समय वहां रहने की कोशिश करता था। उसके बाद जीरो आवर (शून्य काल) का एक घंटा। जहां सदस्य बिना पूर्व नोटिस के लोकहित का कोई मुद्दा उठा सकता था।दोनों सदनों की प्रेस गैलरी इन दो घंटों में पूरी भरी रहती थी। मगर अब खाली ही नहीं कई बार बिना एक भी पत्रकार के भी होती है। संसद का यह रूप बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। संसद ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। मगर अब कम अवधि के संसद सत्र बुलाकर सरकार यहां भी जवाबदेही से बच रही है। संसदीय लोकतंत्र में आदर्श स्थित यह मानी जाती है कि साल में कम से कम सौ दिन संसद चले। मगर अब तो इसके आधे दिन भी नहीं चलती। और यह केवल संसद के लिए नहीं है सभी विधानमंडलों के लिए है। मगर विधानसभाओं की हालत तो और बुरी है। वहां तो हफ्तों के नहीं दिनों के सत्र होने लगे हैं। अगर संविधान में बजट संसद और विधानमंडलों से पास करवाने की मजबूरी नहीं होती तो शायद सरकारें सत्र बुलाती ही नहीं।संसद और विधानमंडल ही ऐसी जगह हैं जहां सरकारों को कानूनन परंपराओं के हिसाब से जवाब देना ही होता है। मगर अब सदन स्थगित कर दो। सत्र चलने ही न दो। यह एक नया चलन शुरू हुआ है जहां सत्ता पक्ष ही सदन नहीं चलने देता। पहले विपक्ष यह काम करता था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने यूपीए के शासन काल के समय यह कहा था कि सदन नहीं चलने देना भी विपक्ष का अधिकार है। एक लोकतांत्रिक तरीका है। मगर अब उन्हीं की पार्टी सत्ता में आ गई है तो सत्ता में रहते हुए सदन नहीं चलने देती। निश्चित रूप से ही इसका एक कारण लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रभावी परफार्मेंस है। राहुल पहले भी बोलते थे। अच्छा बोलते थे। मगर पिछले साल जून से जब से राहुल नेता प्रतिपक्ष बने हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नाक में दम कर रखा है। यहां तक बोल दिया कि अगली बार जब में बोलूंगा तो प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठेंगे नहीं। राहुल जनता के सारे सवाल उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री वैसे तो आते नहीं मगर जब कभी आकर बैठ जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष के किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो पत्रकारों के सवाल के जवाब देना तो दूर उनके सवाल ही नहीं लेते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कान्फ्रेंस तो करते नहीं। सब प्रधानमंत्री करते थे। जिन्हें मौन कह कहकर मोदी ने सरकार बना ली वे मनमोहन सिंह भी करते थे। और हर सवाल का जवाब देते थे। मगर मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कान्फ्रेंस नहीं की। जवाब देने का सवाल ही नहीं। यह मौका आता है जब वे पत्रकारों के सामने होते हैं। परंपरा है कि सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री पत्रकारों से बात करते हैं। मोदी सामने तो आते हैं मगर अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। 11 साल में हर बार ऐसा ही किया। साल में तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र,मानसून सत्र और यह शीतकालीन सत्र। इनके पहले दिन सुबह दस बजे प्रधानमंत्री संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते थे। आम तौर पर संसद में क्या रहने वाला है, सरकार कौन से मुख्य विधेयक लेकर आने वाली है आदि पर। या देश के या अन्तरराष्ट्रीय किसी बड़े तात्कालिक मुद्दे पर भी। प्रधानमंत्री पहले अपनी बात कहने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते थे। मगर मोदी सिर्फ अपनी बात कहकर चल देते हैं। और अपनी बात में भी विपक्ष पर आरोप। एक दिसबंर सोमवार को भी देखना होगा ।

जिहाद की बौद्धिक जड़ों पर सभ्य समाज प्रायरू चुप

बलबीर पुंज

जिहाद की बौद्धिक जड़ों पर सभ्य समाज प्रायरू चुप रहता है, जबकि जिहाद से निर्णायक संघर्ष तभी संभव है, जब उसके मूल विचारों पर सीधी बहस की जाए। क्या मौजूदा दौर में ऐसा संभव है?ज् कश्मीरी डॉक्टर उमर नबी, अनंतनाग अस्पताल में डॉक्टर आदिल अहमद राठर, फरीदाबाद के अल–फलाह अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और लखनऊ निवासी महिला डॉक्टर शाहीन सईद जैसे शिक्षित, संपन्न और समाज में मान–सम्मान पाने वाले मुस्लिमों ने यह मार्ग क्यों अपनाया? 10 नवंबर की शाम राजधानी दिल्ली एक फिदायीन आतंकी हमले से दहल उठी। लालकिला मेट्रो स्टेशन के बाहर चलती कार में हुए भीषण विस्फोट से कई निर्दोष हताहत हो गए। यह हमला एक बार फिर से जिहाद पर बनी पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रहा है। साथ ही यह भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर सभ्य समाज इसपर आजतक निर्णायक विजय क्यों नहीं पा सका है? पिछले कुछ दशकों में भारत जब भी आतंकवाद का शिकार हुआ, तब इसे वामपंथी मुस्लिम समाज में व्याप्त श्अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबीय से जोड़ देते है। यदि ऐसा ही है, तो कश्मीरी डॉक्टर उमर नबी, अनंतनाग अस्पताल में डॉक्टर आदिल अहमद राठर, फरीदाबाद के अल–फलाह अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और लखनऊ निवासी महिला डॉक्टर शाहीन सईद जैसे शिक्षित, संपन्न और समाज में मान–सम्मान पाने वाले मुस्लिमों ने जिहाद का मार्ग क्यों अपनाया? दरअसल, इस्लाम में जिहादी सोच को मजबूती देने में मदरसा शिक्षा पद्धति की बड़ी भूमिका है। अधिकतर मुस्लिम परिवारों के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा–दीक्षा यही ग्रहण करते है, जिसका माहौल कट्टरपंथी इस्लामी पहचान तक सीमितकृ अर्थात् श्काफिर–कुफ्र–शिर्कय अवधारणा से युक्त और सह–अस्तित्व प्रेरित बहुलतावाद से मुक्त रहता है। अक्सर आधुनिकीकरण के नाम पर मदरसों में छात्रों को गणित, विज्ञान और कंप्यूटर आदि विषयों को भी पढ़ाया जाता है। वास्तव में, यह विषय केवल माध्यम हैंकृ इनका उपयोग या दुरुपयोग लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि डॉ.उमर, डॉ. आदिल, डॉ.मुजम्मिल और डॉ.शाहीन आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जिहाद का रास्ता नहीं छोड़ पाए। भारत सहित शेष विश्व में इस तरह के उच्च–शिक्षित (डॉक्टर–प्रोफेसर सहित) जिहादियों की एक लंबी फेहरिस्त है। न्यूयॉर्क के भीषण 9ध्11 आतंकी हमले के गुनहगार (लादेन सहित) आधुनिक शिक्षा में दक्ष थे। कड़वा सच यह है कि जब जिहादी मानसिकता का मेल विज्ञान–गणित–कंप्यूटर से होता है, तो वह और भी अधिक खतरनाक हो जाता है। दिल्ली में हालिया जिहादी हमले की कड़ियां कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तरप्रदेश तक जुड़ी है। जम्मू–कश्मीर पुलिस ने डॉ.आदिल को श्रीनगर की दीवारों पर आतंकी संगठन श्जैश–ए–मोहम्मदय के पर्चे चिपकाने के आरोप में 6 नवंबर को उत्तरप्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने अस्पताल स्थित उसके लॉकर की तलाशी ली, तो वहां से एके–47 सहित कई हथियार बरामद हुए। पूछताछ में डॉ.मुजम्मिल का नाम सामने आया, जिसके फरीदाबाद स्थित किराए के मकान से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक, हथियारों का जखीरा और बम बनाने के उपकरणों को जब्त किया गया। इसी कार्रवाई में पुलिस ने डॉ.शाहीन को भी घातक हथियारों के साथ धरदबोचा। हालिया जिहादी वारदात में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, उसे बकौल जांचकर्ता डॉ.उमर चला रहा था। यह जिहादी मानसिकता केवल फिदायीन हमले तक सीमित नहीं है। गुजरात पुलिस ने हाल ही में डॉ.अहमद मोहिउद्दीन सैयद को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था। सैयद अरंडी के बीजों से घातक राइसिन जहर बना रहा था, जिसे पानी–भोजन में मिलाकर बड़े नरसंहार को अंजाम देने की योजना थी। क्या धन–दौलत के लिए मुस्लिम समाज का एक वर्ग जिहाद का रास्ता अपनाता है? सच तो यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप (भारत सहित) में एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उन्हीं इस्लामी आक्रांताओंकृ गजनवी, गोरी, बाबर, औरंगजेब, अब्दाली, टीपू सुल्तान आदि को अपना श्नायकय या फिर स्वयं को उनका श्वैचारिक–उत्तराधिकारीय मानता है, जिन्होंने श्काफिर–कुफ्रय चिंतन से प्रेरित होकर भारत में असंख्य हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनकी महिलाओं से बलात्कार किया, उनके हजारों मंदिरों को तोड़ा और सांस्कृतिक प्रतीकों–मानबिंदुओं को रौंदा। इस वर्ग की धारणा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अधूरे श्गजवा–ए–हिंदय का मजहबी दायित्व उसपर है। वास्तव में, बीते दशकों में हुए अनेकों जिहादी हमलों (26ध्11 सहित) की प्रेरणा और शताब्दियों पूर्व भारत में इस्लामी आक्रांताओं का चिंतनकृ एक ही है। इसका एक विवरण वर्ष 1908 में जी.रुस–केपेल और काजी अब्दुल गनी खान द्वारा अनुवादित श तारीखा–ए–सुलतान महमूद–ए–गजनवीय पुस्तक में मिलता है। इसके अनुसार, जब महमूद गजनवी (971–1030) को एक पराजित हिंदू राजा ने मंदिर नष्ट नहीं करने के बदले अपार धन देने की पेशकश की, तो उसने कहाकृ हमारे मजहब में जो कोई मूर्तिपूजकों के पूजास्थल को नष्ट करेगा, वह कयामत के दिन बहुत बड़ा इनाम पाएगा और मेरा इरादा हिंदुस्तान के हर नगर से मूर्तियों को पूरी तरह से हटाना हैज। इसी प्रकार वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण कर लाखों निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार करने वाले तैमूर ने अपनी आत्मकथा श्तुजुक–ए–तैमूरीय में लिखा थाकृ हिंदुस्तान आने का मेरा एक उद्देश्य काफिरों से जिहाद और सवाब अर्जित करना है। यहां तक, बाबर ने जिहाद की बुनियाद पर श्काफिरय हिंदू राजा राणा सांगा को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की और खुद को श्गाजीय घोषित किया था। बीते कुछ समय से एक और विषाक्त नैरेटिव बनाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज में व्याप्त श्असहिष्णुताय, श्कट्टरताय और श्आक्रमकताय को मोदी सरकार की नीतियों से जोड़ दिया जाता है। यदि ऐसा है, तो 1947 में देश का मजहब के नाम पर रक्तरंजित विभाजन क्यों हुआ? क्यों इसे गांधीजी–नेहरू–पटेल नहीं रोक पाए? 1980–90 के दौर में मुस्लिम बहुल घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार–पलायन क्यों हुआ? क्यों कोलकाता (1993), भारतीय संसद (2001), गांधीनगर (2002), मुंबई (1993, 2006, 2008 और 2011), कोयंबटूर (1998), दिल्ली (2005 और 2008), जयपुर (2008), अहमदाबाद (2008), पुणे (2010), वाराणसी (2010), हैदराबाद (2013), बोधगया (2013) आदि शहरों में जिहादी हमले हुए? वास्तव में, यह सभी आतंकवादी कृत किसी श्उकसावेय का परिणाम नहीं, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि वर्तमान भारत में आज भी श्मूर्तिपूजाय और श्बहुलतावादय स्वीकार्य है, जिसे जिहादी अवधारणा में श्अक्षम्य अपराधय माना गया है, जिसकी सजा केवल मौत है। भारत वह भूमि है, जहां परंपरा–आधुनिकता साथ–साथ चलती हैं और अनादिकाल से संवाद की स्वतंत्रता है। इसलिए वेद, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति आदि ग्रंथों पर खुली चर्चा होती है। परंतु यह खुलापन इस्लाम में नहीं हैकृ जिसका दंश नूपुर शर्मा, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी आदि झेल रहे है। जिहाद की बौद्धिक जड़ों पर सभ्य समाज प्रायरू चुप रहता है, जबकि जिहाद से निर्णायक संघर्ष तभी संभव है, जब उसके मूल विचारों पर सीधी बहस की जाए। क्या मौजूदा दौर में ऐसा संभव है?

दिसंबर से गृहकर और जलकर का एक होगा बिल

लखनऊ, (संवाददाता)। दिसंबर से शहरवासियों को गृहकर और जलकर का बिल जमा करने के लिए अलग–अलग ऑफिसों में नहीं जाना पड़ेगा। एनआईसी (नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर) ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसकी सिक्योरिटी ऑडिट का काम चल रहा है। जल्द ही उपयोग भी शुरू हो जाएगा। इस नई सुविधा से करीब साढ़े पांच लाख भवनस्वामियों को फायदा होगा। शासन ने करीब 15 वर्ष पहले जल संस्थान का नगर निगम में विलय कर दिया था। इसके बाद जल संस्थान नगर निगम का एक विभाग बन गया। इसे जलकल नाम दिया गया, लेकिन इससे कोई खास अंतर नहीं आया। दोनों का कामकाज पहले की तरह अलग–अलग चलता रहा। जलकल में महाप्रबंधक का शासन चलता है और उसका अपना अलग बजट भी है। जलकर और सीवर कर की वसूली भी जलकल विभाग खुद ही कराता है। उसका बिल भी अलग ही जारी किया जाता है। विलय की कमियों को दूर कर गृहकर और जलकर का बिल एक करने के लिए पहले कई बार कागजी कवायद हो चुकी है, मगर शासन स्तर पर ठोस पहल न होने से इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। करीब छह महीने पहले शासन ने गृहकर और जलकर का बिल एक करने का नया आदेश जारी किया, जिसके बाद एनआईएसी ने दोनों विभागों का डेटा मैचकर सॉफ्टवेयर तैयार किया है। जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि उनका विभाग करीब साढ़े पांच लाख भवनों से जलकर व सीवर कर वसूलता है। इन भवनों को नगर निगम के गृहकर रिकॉर्ड में दर्ज भवनों से मैच किया गया, क्योंकि जलकल उन्हीं भवनों से जलकर लेता है, जिसके 100 मीटर के दायरे में पानी या सीवर की लाइन मौजूद हो। जिन इलाकों में यह सुविधा नहीं है, वहां जलकर नहीं लिया जाता। दूसरी ओर, नगर उन सभी घरों से गृहकर लेता है, जो उनकी सीमा में हैं। इनकी संख्या करीब साढ़े सात लाख है। सिर्फ उन्हीं भवनों को छूट है जो सीमा विस्तार के बाद दायरे में आए हैं और वहां अभी पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है। पबिल एक करने का अपडेटेड सॉफ्टवेयर एनआईसी ने तैयार कर लिया है।

लखनऊ में डॉ. शाहीन के घर पर एनआईए की छापेमारी

लखनऊ, (संवाददाता)। दिल्ली धमाकों से जुड़े संदिग्धों की जांच के लिए सोमवार को एनआईए की टीमों ने कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आठ जगहों पर छापेमारी की। लखनऊ में एनआईए की टीम लखनऊ के खंदारी बाजार स्थित डॉ. शाहीन शाहिद के पिता के आवास पर जांच करने पहुंची। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद रही। इस दौरान इलाके में काफी हलचल रही। बता दें कि दिल्ली धमाकों के संदर्भ में जांच टीम ने लखनऊ में डॉ. शाहीन के परिजनों से पूछताछ की थी। यूपी में एनआईए ने नवंबर के पहले सप्ताह में सहारनपुर से

गिरफ्तार किए गए डॉ. अदील अहमद राथर के आवास की भी तलाशी ली। इन छापों का उद्देश्य श्व्हाइट–कॉलरश आतंकी मॉड्यूल के नेटवर्क का पर्दाफाश करना और इसके संचालन के तरीके को समझना है। व्हाइट–कॉलरश आतंकी मॉड्यूल का तात्पर्य ऐसे आतंकी समूहों से है जो पारंपरिक तरीकों के बजाय वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य सफेदपोश अपराधों के माध्यम से धन जुटाते हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार के मॉड्यूल का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है।

संक्षिप्त खबरें

संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

लखनऊ, (संवाददाता)। अमेठी जिले के पीपरपुर के दुर्गापुर गांव में सोमवार की सुबह एक विवाहिता मृत अवस्था में मिली। रवींद्र वर्मा की पत्नी सपना वर्मा (25) का शव कमरे में गमछे से लटका मिला। सपना के मायके पक्ष ने इस मृत्यु को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग उठाई है। सूचना पर पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची। टीम ने कमरे का निरीक्षण

किया और साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में मामला कई बिंदुओं पर आधारित दिखा है। मायके पक्ष ने कहा कि घटनास्थल की स्थिति सामान्य नहीं लग रही, इसलिए सभी पहलुओं की जांच आवश्यक है। सपना की शादी तीन वर्ष पहले हुई थी। मौत के कारण पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। इंस्पेक्टर श्रीराम पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होगी। परिजनों के बयान सहित सभी संबंधित बिंदुओं की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में होने वाली शिक्षकों की रैली रद्द

लखनऊ, (संवाददाता)। दस प्रदेशों के शिक्षक संगठन श्टीचर फेडरेशन ऑफ इंडियाश (टीएफआई) की पांच दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली की अनुमति को दिल्ली पुलिस ने निरस्त कर दिया है। अब सोमवार को शिक्षक संगठन ऑनलाइन बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। देशभर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद यूपी समेत दस राज्यों

ने टीएफआई का गठन किया था। साथ ही टीईटी अनिवार्यता समाप्त किए जाने के लिए पांच दिसंबर को दिल्ली में रैली करने की घोषणा की थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पांच दिसंबर को रैली की अनुमति निरस्त कर दी है।

आवंटियों की सुविधा के लिए एलडीए लगाएगा लोन मेला

लखनऊ, (संवाददाता)। आवंटियों की सुविधा के लिए एलडीए सोमवार को गोमतीनगर स्थित कार्यालय में लोन मेला लगाएगा।

जहां सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों की टीम उपस्थित रहेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन दिलाया जाएगा। एलडीए दिसंबर में ही रजिस्ट्री शिविर भी लगाएगा। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि कई बार आवंटी सही जानकारी न मिलने व बैंक से लोन न मिलने के कारण संपत्ति का पूरा पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। इससे आवंटियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ तो पड़ता ही है, देरी होने पर आवंटन निरस्त होने का खतरा भी रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को लोन मेला लगाया जा रहा है। जहां एक ही स्थान पर बैंक सहायता मिलेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी भी दी जाएगी। ज्यादा बैंकों की प्रतिस्पर्धा होने पर आवंटी को ब्याज दर का भी फायदा होगा। लोन लेने के लिए आवंटियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय एवं जाति प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवंटियों को बैंक से लोन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोन मेले में एक ही छत के नीचे उनका सारा काम हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री आवास, सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना, पहले आओ–पहले पाओ योजना, अनंत नगर योजना के साथ ही अन्य योजनाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्ति लेने वाले आवंटी बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्लोन मेले में आवंटियों की ऋण संबंधी जरूरतें पूरी होंगी और वे पूरा भुगतान कर अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे। दिसंबर में रजिस्ट्री शिविर भी लगाया जाएगा। इसके लिए फाइलें तैयार की जा रही हैं।

बिजली के 1,13,758 डिफाल्टर, घर, दुकान, कार्यालय पहुंचेगा नोटिस

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में गांव से लेकर शहर तक 1,13,758 बिजली डिफाल्टर चिह्नित हुए हैं। इन पर लगभग 842 करोड़ रुपये की देनदारी है। इनमें 72,748 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने बिजली तो जलाई, मगर बिल नहीं चुकाया, जबकि 41,010 उपभोक्ता बिजली चोरी के मामलों में पकड़े गए हैं। ऐसे सभी बकायेदारों के लिए पावर कॉर्पोरेशन बिजली बिल राहत योजना (एकमुश्त समाधान योजना) लेकर आया है। एक दिसंबर से शुरू हो रहे पहले चरण में डिफाल्टरों के 100: ब्याज माफ किए जाएंगे और मूल रकम पर भी 25: की छूट मिलेगी। सभी बकायेदारों के नोटिस तैयार होकर कार्यालयों तक पहुंच चुके हैं। सोमवार से इन नोटिसों को

डिफाल्टरों के घर, दुकान, कार्यालय भेजने का काम शुरू हो जाएगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शहर से लेकर गांव तक सभी जनसुविधा एवं बिलिंग केंद्रों पर पंजीकरण होगा। उपभोक्ता सिर्फ अपना खाता नंबर देकर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उन्हें एकमुश्त भुगतान या किश्तों में कितना लाभ मिलेगा। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम के अनुसार, निगोहां से रहीमाबाद और बंथरा–हरौनी से आलमबाग तक कुल बिजली चोरी में फंसे 29,111 उपभोक्ताओं पर करीब 414 करोड़ रुपये बकाया है।

संक्षिप्त खबरें

सिर में चोट में लगने पर जरूरी है सूजन की स्थिति आंकना

लखनऊ, (संवाददाता)। संजय गांधी पीजीआई में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रमुख प्रो. एके जैसवाल के मुताबिक सिर में चोट लगने की स्थिति में मस्तिष्क में सूजन की स्थिति का आकलन बहुत जरूरी है। विभागाध्यक्ष रविवार को संस्थान में हुई इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख प्रो. अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मरीजों की सेहत के लिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इससे गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद मिलती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग सिर की चोट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क की अन्य समस्याओं के कारण होने वाली सूजन का पता लगाने के लिए की जाती है। सूजन की वजह से सिर के अंदर दबाव बढ़ने से मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। इस प्रक्रिया में, खोपड़ी के अंदर एक छोटा सेंसर या कैथेटर डाला जाता है जो दबाव की निरंतर रीडिंग करता रहता है। इस मौके पर डॉ. रथजीत मित्रा, डॉ. सौमिल जैसवाल, डॉ. अंकुर बजाज, डॉ. संगम यादव और डॉ. दिशा रानी, डॉ. पवन कुमार वर्मा और डॉ. सौमेन कांजीलाल मौजूद रहे।

रोडवेज संविदा चालकों की भर्ती

लखनऊ, (संवाददाता)। रोडवेज संविदा चालकों की भर्ती सोमवार से शुरू होगी। इसके लिए कमता बस अड्डे पर रोजगार मेला लगाया जाएगा। यह दो दिवसीय मेला होगा। इसमें 120 संविदा चालकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने बताया कि संविदा बस चालकों की भर्ती एक व दो दिसंबर को होगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा छह और न्यूनतम आयुसीमा 23 वर्ष छह माह रखी गई है। हैवी वाहन लाइसेंस के साथ दो साल का अनुभव होना चाहिए। संविदा चालकों को 2.06 रुपये प्रति किमी पारिश्रमिक मिलेगा। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में निधन होने पर साढ़े सात लाख रुपये, घायल होने पर दस हजार रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के लिए 25 हजार रुपये मिलेंगे। रोजगार मेले में आने वाले इच्छुक अभ्यर्थी दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र, लाइसेंस, आधार कार्ड, पैनकार्ड की छायाप्रति लेकर पहुंचें। भर्ती सुबह दस से शाम पांच बजे तक चलेगी। पहले टेस्ट में पास होने पर दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर स्थित प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान एलेन फॉरेस्ट भेजा जाएगा।

नई श्रम संहिताएँ लागू श्रमिकों को सुरक्षा और उद्योगों को मिलेगी सरल व्यवस्था

लखनऊ, (संवाददाता)। लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि भारत सरकार ने देश की पुरानी श्रम व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार करते हुए 29 पुराने श्रम अधिनियमों को एकीकृत कर चार नई श्रम संहिताएँकृमजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020कृको लागू कर दिया है। ये सभी संहिताएँ 21 नवम्बर 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी हैं।उन्होंने कहा कि नई संहिताएँ श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराते हुए देश की श्रम प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और सरल बनाएंगी।मंत्री राजभर ने बताया कि इन सुधारों से न केवल जटिल प्रक्रियाएँ कम हुई हैं, बल्कि उद्योगों के लिए अनुपालन का बोझ भी काफी घटा है। पहले जहाँ 1228 धाराएँ थीं, अब उनकी संख्या घटाकर 480 कर दी गई है। 1436 नियमों की जगह अब केवल 351 नियम लागू होंगे। 84 रजिस्टरों के स्थान पर मात्र 8 रजिस्टर और 31 रिटर्न की जगह एकल रिटर्न की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यवसायों को राहत मिलेगी, जबकि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।उन्होंने बताया कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। रैंडमाइज्ड निरीक्षण प्रणाली के लागू होने से 'इंस्पेक्टर राज' की अवधारणा समाप्त होगी और निरीक्षक की भूमिका 'फैसिलिटेटर' के रूप में विकसित होगी। पहली बार के उल्लंघन पर नियोक्ता अधिकतम जुर्माने के 50 प्रतिशत का भुगतान कर राहत पा सकेंगे, जिससे अनावश्यक मुकदमों से बचाव होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा।मजदूरी संहिता पर जानकारी देते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि वेतन की परिभाषा को एकीकृत कर दिया गया है और न्यूनतम वेतन अब संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। वेतन भुगतान की समयसीमा अनिवार्य की गई है और सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिन के भीतर सभी देय भुगतान सुनिश्चित होंगे। ओवरटाइम पर दोगुना वेतन, वेतन कटौती की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत और सभी कर्मचारियों को वेज–स्लिप उपलब्ध कराना अब अनिवार्य होगा।सामाजिक सुरक्षा संहिता पर उन्होंने बताया कि पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। इनके लिए एक विशेष कोष का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ–साथ एग्रीगेटर्स भी अपने टर्नओवर का 1/2 प्रतिशत योगदान करेंगे। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ प्राप्त होंगे और एक वर्ष की सेवा पर ग्रेच्युटी का अधिकार मिलेगा। श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी पात्रता अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है। निजी आवास निर्माण सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है।औद्योगिक संबंध संहिता के बारे में उन्होंने बताया कि 300 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी या बंदी के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल किया गया है और 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना कोई भी हड़ताल, तालाबंदी या अवकाश प्रतिबंधित होगा। उद्योगदृश्रमिक समन्वय मजबूत करने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का गठन किया गया है।उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता में कारखानों, खदानों, बागानों, भवन निर्माण, पत्रकारिता और सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कार्यस्थल की उपयुक्तता से संबंधित सभी प्रावधानों को एकीकृत कर आधुनिक स्वरूप दिया गया है। सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर कैरियर केंद्र स्थापित करेगी जहाँ युवाओं के पंजीकरण, परामर्श, काउंसलिंग और रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित होगी मंत्री राजभर ने विश्वास व्यक्त किया कि नई संहिताएँ रोजगार विस्तार, उद्योग विकास और श्रमिक कल्याण को नई दिशा देंगी।इस अवसर पर प्रमुख सचिव एम.के. शन्मुगासुंदरम, विशेष सचिव कुणाल सिल्कू, निदेशक बॉयलर संदीप गुप्ता, अपर श्रम आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव, उप श्रम आयुक्त शमीम अख्तर, पंकज राणा, अजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

लखनऊ योग भवन की 65 वर्ष की साधना– सम्मान समारोह और भरत नाट्यम प्रस्तुति के साथ मनाया गया विशेष आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रतिष्ठित योग भवन पिछले 65 वर्षों (1960–2025) से योग, चिकित्सा योग और ध्यान के क्षेत्र में निरंतर सेवा कर रहा है। जब देश में योग आज की तरह लोकप्रिय नहीं था, तब भी योग भवन ने समर्पण, ईमानदारी और लगन के साथ लोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने का कार्य शुरू किया था। छह दशकों से अधिक समय तक लगातार सक्रिय रहना किसी भी संस्थान के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, और योग भवन ने यह उपलब्धि समाज की सेवा करते हुए अर्जित की है।योग भवन के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन 2002 में

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल विष्णु कांत शास्त्री द्वारा किया गया था। अपनी समृद्ध यात्रा के 65वें वर्ष पर 29 नवम्बर 2025 को संस्थान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गुरु जी सुधीर शर्मा, जो करीब 50 वर्षों से योग भवन की सेवा और संचालन से जुड़े हैं, ने संस्थान के पूर्व योग शिक्षकों और सहयोगी कर्मचारियों को सम्मानित कर उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम के बाद प्रसिद्ध कलाकार कलाश्री सैयद शमशुर रहमान और उनके दल द्वारा भगवान शिव पर आधारित भरतनाट्यम प्रस्तुति की गई, जिसने दर्शकों को मोह लिया।समारोह के समन्वयक और योग एवं ध्यान विशेषज्ञ सौमिल शर्मा ने कहा कि "योग गुरु–शिष्य परंपरा पर आधारित अमूल्य विरासत है, ठीक वैसे ही जैसे भारत विश्व का योग गुरु है। तनावमुक्त जीवनशैली के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए।"योग भवन की निदेशक अरुणा शर्मा ने बढ़ते तनाव, अपराध और हिंसा के दौर में योग और ध्यान की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज के समय में यह पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उनके अनुसार, योग न केवल रोगों को ठीक करने में सहायक है, बल्कि तनाव, चिंता, अवसाद को कम करने और ऋतु परिवर्तन के समय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी अत्यंत प्रभावी है।उन्होंने बताया कि लोग साइनसाइटिस, सर्दी–खांसी, एलर्जी, रक्तचाप, कम प्रतिरोधक क्षमता से होने वाले बुखार, अवसाद के दौर, मौसम बदलने से बढ़ने वाले जोड़ दर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। ऐसे में प्रतिदिन 25/30 मिनट का योग अभ्यास एक मजबूत शरीर, संतुलित मन और शांत आत्मा के लिए पर्याप्त है। आधुनिक जीवनशैली की चुनौतियाँकृजंक फूड, पानी की कमी, अनिद्रा, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक दायित्वकृ स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, और योग इन सबके बीच संतुलन बनाने का सरल मार्ग है, जिसके लिए किसी उपकरण या आर्थिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती।समारोह में गुरु जी सुधीर शर्मा ने जिन वरिष्ठ सदस्यों और सहयोगियों को सम्मानित किया, उनमें शामिल हैं।

लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस पर भव्य राज्य स्तरीय समारोह

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि योगी सरकार दिव्यांगजन के समग्र विकास, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी उद्देश्य के तहत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 3 दिसम्बर, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।मंत्री कश्यप ने बताया कि समारोह में दिव्यांगजन सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान सामाजिक संवेदनशीलता और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 500 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक सुविधा और आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। इसके साथ ही विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत 36 मेधावी छात्र–छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा।मंत्री ने बताया कि 3 से 5 दिसम्बर 2025 तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी दिव्यांगजन की कलात्मक, तकनीकी, व्यावसायिक एवं उद्यमशील क्षमताओं पर आधारित होगी। इस अवसर पर दिव्यांग कलाकारों और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जो समाज में समावेशी दृष्टिकोण को प्रेरित करेंगे।कार्यक्रम के दौरान आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव में दिव्यांगजन कल्याण को बढ़ावा देने हेतु 28 बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमंत्रित की गई हैं।

यातायात माह दिवस के बीत जाने के बावजूद जाम से नही निजात पा रहे शहरवासी

अयोध्या। यातायात माह दिवस बीत जाने के बावजूद भी शहर के विभिन्न चौराहों तथा मार्गो पर जाम लगा रहता है।जो घंटो बना रहता है।इस समय शहर मे यातायात व्यवस्था राम भरोसे यातायात चल रही है।जबकि इस समय यातायात माह दिवस बीत गया।परंतु इसके बावजूद शहर का कोई ऐसा ही चौराहा या फिर मार्ग शायद ही बचा हो जहां पर आपको जाम ना मिले।और यह जाम केवल कुछ मिनट तक ही नहीं बल्कि कई घंटों तक आप इस जाम में फंसे रहेंगे यहां तक की इधर से गुजरने वाले खासकर एंबुलेंस के माध्यम से मरीज छात्रों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है।इस संबंध में जब यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका यही रटा रटाया उत्तर रहता है कि जाम की कोई समस्या शहर मे नहीं है।कोतवाली नगर क्षेत्र के कसाबबाडा, रिकाबगंज, जिला महिला चिकित्सालय, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, देवकाली बाईपास, नाका बाईपास, रायबरेली बाईपास मार्ग, चौक, फतेहगंज, रिकाबगंज, नियांवा,गुदरी बाजार सहित कई ऐसे प्रमुख चौराहे व मार्ग हैं जहां पर जाम लगना आम बात है।और यह जाम सुबह देर शाम तक बनी रहती है।जिसके चलते स्कूली बच्चे, मरीज, बाहर से आने वाले श्रद्धालु व अन्य राहगीर, दो पहिया व चार पहिया वाहन चालक इस जाम मे घंटो फंसे रहते है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी ध्यान नहीं दे रहे है।देखा जाये तो इन चौराहों पर आपको एकाद यातायात के सिपाही मिलेंगे।आधा चौराहा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ना तो यातायात सिपाही तैनात मिलेंगे और ना ही यातायात ट्रैफिक लाइट से भीड़ को कंट्रोल करते हुए मिलेगी।इस संबंध में जब यातायात एसपी एपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया की विभाग में यातायात पुलिस कर्मी पर्याप्त संख्या में है लेकिन प्रमुख चौराहों पर यातायात का नियंत्रण ट्रैफिक लाइट द्वारा होता है।

बिना सूचना करंट छोड़ने से लाइनमैन की मौत

ब्यूरो चीफ रू आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। लम्भुआ थाना क्षेत्र के गरये गांव में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सराय अचल (कोतवाली देहात) निवासी घनश्याम यादव (45 वर्ष) की उस समय मौत हो गई, जब वे 11 हजार वोल्ट लाइन पर सिटडाउन लेकर काम कर रहे थे और विभाग की ओर से अचानक बिना सूचना बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। मृतक संविदा पर ठेकेदार संदीप शर्मा के अधीन काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घनश्याम पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक कर रहे थे, तभी अचानक तेज करंट प्रवाहित होते ही वे बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर पड़े। साथी कर्मियों ने उन्हें तुरंत सीएचसी लम्भुआ पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग ने लाइन क्लियरेंस, सुरक्षा प्रोटोकॉल और परमिट–टू–वर्क जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं की पूरी तरह अनदेखी की। उनका कहना है कि जब कोई लाइनमैन सिटडाउन लेकर काम कर रहा होता है, तब सप्लाई बहाल करना विभागीय आपराधिक लापरवाही है। मृतक के भाई राधेश्याम यादव ने थाना लम्भुआ में थ्न दर्ज कराने की तहरीर दी है, लेकिन आरोप है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इससे परिजनों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों ने दोषी जेई, एसडीओ सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने इसे विभागीय लापरवाही से हुई मौत बताते हुए दोषियों के निलंबन, गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की मांग की है।

संक्षिप्त खबरें

सेवा निवृत्त शिक्षक का एटीएम कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकाले

सुलतानपुर। शहर के शास्त्री नगर निवासी सेवा निवृत्त शिक्षक जगन्नाथ मौर्य का एटीएम कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकाल लिए गए। वह सोमवार दोपहर सिटी नर्सिंग होम के पास एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकालने गए थे। पीछे से आए एक युवक ने उन्हें झांसा देकर एटीएम कार्ड बदल लिया और उनके खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जिले मे 109 परीक्षा केंद्र हुए प्रस्तावित - डीआईओएस

अयोध्या।जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वर्ष 2026 की यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां करने में जुट गया है। इस संबंध में डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा को संपन्न करने के लिए इस बार जिले में कुल 109 कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है।वहीं पिछले वर्ष बने 16 परीक्षा केदो को इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा।जबकि इस बार इनके स्थान पर दूसरे नये 16 कालेज को परीक्षा केंद्र बनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।बताया कि इस बात प्रस्तावित परीक्षा केदो की सारी सुविधा की जांच परख की जा रही है।वही बोर्ड परीक्षा प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस बार जिले में सबसे अधिक मिल्कीपुर में कुल 31, सदर में 23, बीकापुर तहसील में 18, सोहावल तहसील में 17 तथा रुदौली तहसील में 20 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित है।उन्होंने बताया कि यह परीक्षा केंद्र की सार्वजनिक सूची डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपद दिए केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण तथा अनुमोदन के के लिए परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है बताया कि ऑनलाइन प्राविधिक से चयनित परीक्षा केदो के संबंध में यदि कोई आपत्ति या शिकायत करता है तो जनपद दिए केंद्र निर्धारण समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर अपना ऑनलाइन प्रतिवेदन माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर 4 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

व्यापारियों से जालसाजी कर ठगी करने वाले एक ठग को रुदौली पुलिस ने किया गिरफ्तार

अयोध्या। सोमवार को व्यापारियों से जालसाजी कर ठगी करने वाले ठग को कोतवाली रुदौली पुलिस गिरफ्तार किया।इस इस संबंध में जानकारी देते हुए को रुदौली आशीष निगम ने बताया कि संबंध में जानकारी देते हुए को रुदौली आशीष निगम ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुदौली संजय मौर्य ने रुदौली पुलिस टीम द्वारा, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर व्यापारी से धोखाधड़ी

करके इनवेस्टमेंट के नाम पर कुल 13 लाख 60 हजार रुपये की ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया।उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को करीमपुर – अकबरगंज रोड पर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया।जिसकी पहचान सुशान्त गुप्ता पुत्र स्व0 सचिद्र प्रकाश निवासी मो0कटरा कस्बा व थाना रुदौली के रुप मे हुई है।बताया कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन,सिम कार्ड व ठगी के कुल 285000/– रुपये बरामद हुए।इस सफलता मे उ0नि0 युवराज सिंह,उ0नि0 ऋषिकेश सिंह,उ0नि0 दयाराम सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

चार साल का रिकार्ड टूटा, इस साल सबसे ठंडा रहा नवंबर

भदोही, (संवाददाता)। कड़ाके की ठंड के चलते नवंबर में चार साल का रिकार्ड टूट गया है। माह के शुरुआती दिनों में बूंदाबांदी होने के बाद से मौसम उत्तर–चढ़ाव भरा रहा। इस साल नवंबर का न्यूनतम तापमान औसतन एक डिग्री कम दर्ज किया गया। इससे पूर्व के वर्षों में नवंबर का औसत तापमान 12 से 14 डिग्री रहता था, जो इस बार 11 डिग्री दर्ज किया गया। इस माह में 14 दिन ऐसे रहे, जब रात का पारा 11 से 12 डिग्री के बीच रहा। तापमान में उतार–चढ़ाव के कारण गलन की स्थिति बनी है। मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2021 में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद से 2022 से 2024 तक माह का औसत तापमान 12 से 14 डिग्री रहा। नवंबर में ठंड का अहसास नहीं हुआ लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि नवंबर के पहले सप्ताह में बूंदाबांदी होने के कारण ठंड में वृद्धि हुई है। दूसरे सप्ताह में जम्मू कश्मीर सहित पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी। इसके कारण माहमर कड़ाके की ठंड की रही। दिसंबर वाली ठंड का अहसास लोगों को नवंबर में हुआ। रातभर लोग ठंड से ठिठुरते रहे। महीने में 14 दिन ऐसे रहे, जब रात का तापमान 11 डिग्री के आसपास रहा। पहली बार नवंबर में आठ से 10 दिनों तक पश्चिम–दक्षिण की हवा चली।

घर में घुसकर महिला से छेड़छाड, बच्ची के सिर पर हथौड़े से किया हमला- मृत समझ भागे

गोरखपुर, (संवाददाता)। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उधार के पैसे लौटाने के बहाने एक युवक रात में महिला के घर में घुस गया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने महिला की 10 वर्षीय बेटी के सिर पर हथौड़े से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़ित महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तिवारीपुर इलाके के मस्जिद गली के पास रहने वाले अफरोज आलम को पैसे उधार दिए थे। 27 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई कि वह उधार के पैसे लौटाने आया है। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, अफरोज जबरन अंदर घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। महिला के विरोध करने पर आरोपी उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोर सुनकर अंदर से उसकी 10 वर्षीय बेटी बाहर आई और मां को बचाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर आरोपी ने अपने साथ लाए हथौड़े से बच्ची के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर गई। महिला किसी तरह पड़ोस की छत पर कूदकर जान बचाने में सफल हुई और अपनी मां को फोन कर वारदात की जानकारी दी। महिला का आरोप है कि इस बीच आरोपी घर में रखे पैसे और कीमती सामान लेकर भाग गया। महिला की मां जब रास्ते में उसे मिलीं तो आरोपी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। घर पहुंचने पर बच्ची खून से लथपथ अचेत अवस्था में मिली। तत्काल डायल 112 को कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बच्ची को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने 29 नवंबर की रात को कोतवाली थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अफरोज आलम के खिलाफ हत्या की कोशिश, यौन उत्पीड़न और लूट समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। बच्ची की हालत में सुधार हो रहा है।

सभी मतदाता अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ, बीएलए को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दे : जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिला निर्वाचन अधिकारीधजिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के द्वारा तहसील शाहगंज के सभागार में मंगलवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा कार्मिको से क्रमवार डिजीटाइजेशन की जानकारी प्राप्त की गई।उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से जुड़ी तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि डिजिटाइजेशन के दौरान मतदाता सूची 2003 से मैपिंग अवश्य करा ले।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप क्रियान्वित की जा रही हैं, डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में बीएलओ के सहयोग के लिए सुपरवाइजर के रूप में लेखपाल, अध्यापक और पंचायत सहायक भी लगाये गये है। उन्होंने बताया कि जनपद में 100 से अधिक बीएलओ के द्वारा शत–प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं, जिन्हे प्रशस्ति पत्र देकर उन्हे सम्मानित किया गया है और भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि आयोग के द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तिथि बढ़ाई है, जिसके क्रम में उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ, बीएलए को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए ससमय कार्य पूर्ण करें और इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी बने। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य में विधानसभा शांहगंज में उत्तम कार्य सम्पादित किये जाने पर उप जिलाधिकारी, बीएलओ, लेखपाल, अध्यापक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यो की सराहना की।

संक्षिप्त खबरें

समाज को एकजुट करने में सहयोग करें युवा : आरके चौधरी

भदोही, (संवाददाता)। ऑल इंडिया युवा शक्ति सेना की ओर से रविवार को नगर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि लखनऊ, मोहनलाल गंज सांसद आरके चौधरी ने महाराजा बिजली पासी व डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लोगों ने 51 किलो का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सांसद चौधरी ने कहा कि पासी समाज आज भी बिखरा हुआ है। उसे समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाते हुए समाज को एकजुट करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पासी समाज के 12 पुराने किले हैं लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया। अगर हमारी सरकार बनी तो उन किलो का सुंदरीकरण कराया जाएगा। लोक कलाकार राजेंद्र यादव व दीनानाथ हंसमुख ने अपने गीतों से समाज के इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मौके पर एसके इंद्रा, जाहिद बेग, गणेश यादव, धर्मेंद्र सरोज, बीरेंद्र सरोज, डॉ. जितेंद्र सरोज, परमेंद्र सरोज, अरविंद सरोज, अच्छेलाल आदि रहे। संचालन जटाशंकर मौर्य ने किया।

संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए तीन केंद्र तय

भदोही, (संवाददाता)। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से साल 2026 में होने वाली प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा तक की परीक्षा के लिए जिले में तीन केंद्र लगभग फाइनल हो गए हैं। परिषद की संस्तुति पर डीआईओएस ने तीनों केंद्रों की सूची जारी कर आपत्तियां मांगी थी, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई है। जिले में कुल 19 संस्कृत माध्यमिक और महाविद्यालय हैं। इस साल परीक्षा में कुल 1049 छात्र–छात्राएं शामिल होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी संग संस्कृत बोर्ड के केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में तीन केंद्र प्रस्तावित कर इसके लिए आपत्तियां मांगी गई थीं। इसके लिए 30 नवंबर तक समय दिया गया था। डीआईओएस अंशुमान ने बताया कि प्रथम और उत्तर मध्यमा स्तर की परीक्षा के लिए ज्ञानपुर तहसील में श्री राजाराम संस्कृत महाविद्यालय जखांव, औराई में शिवशंकर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोसियां और भदोही तहसील में श्री संकट मोचन संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरियावां को केंद्र बनाया गया है। केंद्रों को लेकर 28 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई थी लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई है।

सबसे ज्यादा चालान के लिए यातायात प्रभारी सम्मानित

भदोही, (संवाददाता)। एक माह तक चले यातायात माह का रविवार को समापन होने के बाद लालानगर टोल प्लाजा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सबसे ज्यादा चालान करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ थानों को सम्मानित किया गया। सबसे ज्यादा 3470 चालान करने वाले यातायात प्रभारी अनिल सिंह को सम्मानित किया गया। यातायात जागरूकता को लेकर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को डीएम शैलेष कुमार, एसपी अभिमन्यु मांगलिक और एएसपी शुभम अग्रवाल ने पुरस्कृत किया।

अब सीएचसी पर मुफ्त में करा सकेंगे 40 जांच

सीतापुर, (संवाददाता)। अब ग्रामीण इलाके के मरीज आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लिवर, किडनी सहित 40 अन्य प्रमुख जांच मुफ्त में करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें निजी सेंटरों पर तीन से चार हजार रुपये नहीं खर्च करने पड़ेंगे। मरीजों की सहूलियत के लिए शासन ने एक कंपनी से अनुबंध किया है। इसके तहत जिले के सभी 22 सीएचसी पर मशीनें व रिजेंट पहुंचा दिया गया है। जल्द ही सभी सीएचसी पर जांच शुरू हो जाएगी। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अभी तक मरीजों को प्राथमिक जांच की ही सुविधा मिलती थी। लिवर, किडनी, ईसीजी सहित अन्य प्रमुख जांच के लिए निजी सेंटर पर जाना पड़ता था। एक चिकित्सक ने बताया कि यदि लिवर व किडनी की समस्या है तो जांच पर कम से कम तीन से चार हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। अब ये सभी जांच सीएचसी में निशुल्क हो सकेंगी। महमूदाबाद सीएचसी में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। अन्य सीएचसी पर भी जल्द शुरू हो जाएगी। जांच के लिए सेलेक्ट्रा मशीन आई है। इसमें एक साथ 45 सैंपल लगाए जाएंगे। इनकी रिपोर्ट 30 मिनट के अंदर आ जाएगी। यदि ये मशीन खराब होती है तो 72 घंटे के अंदर इसे सही किया जाएगा। एक साल का एडवांस रिजेंट उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही अनुबंधित कंपनी का एक कर्मचारी भी तैनात रहेगा।

आधे घंटे में मिल जाएगी रिपोर्ट

मरीजों को रिपोर्ट लेने में भी आसानी रहेगी। आधे घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मिलेगी। मरीज इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। इससे मरीजों को जांच के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीएचसी में जिस दिन जांच कराएंगे, उसी दिन इलाज भी मिल जाएगा।

अब बाहर जाने की जरूरत नहीं

महमूदाबाद सीएचसी अधीक्षक डॉ. आशीष ने बताया कि लिवर की जांच करीब 700 रुपये में होती है। इसी तरह किडनी की जांच के लिए करीब एक हजार रुपये खर्च करने होते है। इंफेक्शन की भी जांच महंगी होती है। सीएचसी में ये सब फ्री में होंगी। खून से संबंधित कोई भी जांच के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

मिलेगा बेहतर इलाज

मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। सीएचसी पर अब सभी प्रकार की निशुल्क जांचों की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मरीजों से अपील है कि वह बाहर से जांच के चक्कर में न पड़ें। विश्वसनीय तरीके से अस्पताल के अंदर ही जांच करवाएं।

व्यापारी के यहां करती थी काम मौत- परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

गोरखपुर, (संवाददाता)। कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर में ऑर्किड ग्रीन अपार्टमेंट के सामने रविवार की शाम 6ब30 बजे एक युवती का शव रखकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर सीओ कैंट के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। परिजनों को समझाकर किनारे किया। युवती कुछ समय पहले तक अपार्टमेंट में ही एक व्यापारी परिवार के घर काम करती थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवती ने बिहार में खुदकुशी की थी। करीब एक घंटे बाद परिजनों से तहरीर लेकर पुलिस ने उन्हें समझाया और अंतिम संस्कार के लिए कुशीनगर भेज दिया। जानकारी के अनुसार, कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कुर्मीपट्टी किरवनिया की नीतू साहनी (21) मोहद्दीपुर के ऑर्चिड अपार्टमेंट में एक व्यापारी परिवार के यहां नौकरानी का काम करती थी। परिजनों का कहना है कि वह पिछले तीन साल से यहां काम कर रही थी। बहन रिशा ने बताया कि शनिवार की सुबह पिता के मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई। बताया गया कि नीतू की तबीयत खराब है और वह कुशीनगर के कप्तानगंज आ जाएं। जब वह कप्तानगंज गए तो वहां से पुलिस बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के भितहा थाना ले गई। इसी क्षेत्र में उसका शव मिला था। वहां पर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को घर लेकर गए और फिर वहां से रविवार की दोपहर में गोरखपुर आ गए। रिशा ने बताया कि दोपहर में अपार्टमेंट के सामने सड़क किनारे पिकअप में शव रखकर व्यापारी से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन वह घर पर नहीं थे। शाम तक इंतजार करने के बाद शव को सड़क पर रख दिया। पुलिस ने 10 मिनट के अंदर शव को किनारे किया। इसके बाद भीड़ ऑर्किड अपार्टमेंट के गेट पर पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि युवती अपार्टमेंट में रहकर काम करती थी तो उसका शव बिहार से कैसे मिला? पिता अयोध्या साहनी ने आशंका जताई कि बेटी की हत्या की गई है। बहन रिशा ने कहा कि नीतू की गर्दन पर रस्सी के निशान थे। हंगामे की सूचना पर पहुंचे सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने परिजनों से बातचीत की और घटना के बारे में जानकारी जुटाई। अपार्टमेंट में रहने वाले व्यापारी से फोन पर बात की। उनका परिवार लखनऊ में किसी शादी समारोह में गया हुआ था। व्यापारी ने बताया कि नीतू 14 अप्रैल को ही काम छोड़कर एक युवक के साथ चली गई थी। घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीओ कैंट ने बताया कि भितहा थाने की पुलिस से बात की गई तब पता चला कि नीतू ने वहां खुदकुशी की थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। नीतू वहीं पर रहकर काम कर रही थी। मृतका के पिता अयोध्या साहनी ने बताया कि उनकी पांच बेटियां व एक बेटा है। वह खेती कर घर का खर्च चलाते थे। नीतू को तीन साल पहले मोहद्दीपुर के ऑर्किड ग्रीन के एक फ्लैट में रहने वाले परिवार के पास घर का काम करने के लिए भेजा था। शुक्रवार को आखिरी बार बेटी से बात हुई थी। तब उसने बताया कि वह गोरखपुर में ही है। तीन महीने पहले ही उसकी शादी तय हुई है। अगले वर्ष उसकी शादी की तैयारी थी। हालांकि, पुलिस की जांच में सामने आया है कि नीतू पिछले कुछ समय से बिहार में ही काम कर रही थी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।